**ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA**
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
**PP. No.- 181-184**

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

# सहकारिता : सतत विकास का एक मॉडल

**ममता**

शोध अध्येत्री– समाजशास्त्र, सी०एस०जे० एम० कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर (उ0प्र0), भारत

**Received-18.05.2023, Revised-23.05.2023, Accepted-27.05.2023 E-mail: yadavmamta0905@gmail.com**

***सारांशः*** ***सहकारिता को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भागीदारों के रूप में मान्यता प्राप्त है। सहकारिता से आशय" एक साथ मिलजुल कर कार्य करना अर्थात एक सब के लिए एवं सब एक के लिए।"***

***इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन (ILO) ने सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में सहकारी मॉडल को सक्रिय रुप से बढ़ावा दिया है। स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने में सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सहकारी आंदोलन को मजबूत करके संपूर्ण विश्व में विकास की गति को तीव्रता प्रदान की जा सकती है। सहकारी समितियां व्यक्तियों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनेकों विकल्प प्रदान करती हुई नजर आ रही हैं। दुनिया नें पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों मॉडलों को अपनाया लेकिन सहकारी मॉडल सबसे उपयुक्त साबित हुआ है। वर्तमान असंतुलित विकास को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सहकारी मॉडल को लोकप्रिय बनाना होगा और इससे ना सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा बल्कि संपूर्ण विश्व को संतुलित विकास को प्राप्त करने में भी सफलता मिलेगी।***

***कुंजीभूत शब्द– सहकारिता, विकास, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सहकारी मॉडल, सक्रिय रुप, स्थानीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर।***

सहकारिता के सात स्वर्णिम सिद्धांत कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संतुलित विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। **यह सात प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं :–**

(1) स्वैच्छिक एवं खुली सदस्यता। (2) सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण। (3) सदस्यों की आर्थिक भागीदारी। (4) स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता। (5) शिक्षा प्रशिक्षण एवं सूचना। (6) सहकारी समितियों के बीच सहयोग। (7) समुदाय के लिए चिंता।

**सहकारी आंदोलन के चार मुख्य निर्देशक सिद्धांत हैं–**

1) सहकार से समृद्धि। 2) समावेशी विकास। 3) सामुदायिक उद्यमिता से आत्मनिर्भरता। 4) सहकारी समितियों से आगे सहयोग।

स्वतंत्रता के पश्चात सहकारिता के लिए आर्थिक विकास के युग का सूत्रपात हुआ एवं साथ ही साथ संतुलित विकास की दिशा में भी कार्य को गति प्रदान की गई।

**क्या है सतत विकास?–** आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। सबसे पहली बार "सतत विकास" शब्द की परिभाषा पर व्याख्या 1987 ईस्वी में WCED( World Commission On Environment and Development) ने OUR COMMON FUTURE नमक रिपोर्ट में की थी। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 (रियो घोषणा) में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया 2002 के जोहांसबर्ग सम्मेलन (रियो10) का मुद्दा ही सतत विकास था। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

**समावेशी विकास के लक्ष्य एवं सहकारिता मॉडल–** संपूर्ण विश्व सहकारी नेतृत्व वाली समग्र सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए सदस्य प्रयासरत रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में मिलता है कि, जिसमें योजना की सफलता का आकलन अन्य चीजों के साथ इस हद तक किया जाना चाहिए कि इनका क्रियान्वयन सहकारी संगठनों के माध्यम से किया गया था। 1960 में सहकारिता के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण विकास को महत्व देते हुए संतुलित विकास पर भी प्रकाश डाला गया था। सहकारी क्षेत्र ने हमेशा से ही अपने सर्व समावेशी दृष्टिकोण के साथ ही देश के समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सहकारिता मॉडल सभी सतत विकास लक्ष्यो को में प्राप्त करने में योगदान कर सकता है क्योंकि यह विविध आर्थिक क्षेत्रों में शामिल है और इसका प्रभाव वैश्विक उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2012 में समावेशी विकास पर आयोजित किए गए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सहकारिता को समावेशी विकास का वाहक करार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं अंतरराष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के मुताबिक सहकारिता मॉडल सभी समावेशी विकास लक्ष्य को हासिल करने में सार्थक सिद्ध हो सकती हैं।

**गरीबी उन्मूलन–** गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अमृत वर्ष 2022 से लेकर वर्ष 2047 के दौरान सहकारी संस्थाओं को गरीबी उन्मूलन में गांव तक पहुंच बनाने को कहा है उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि सहकारी संस्थाओं को पारदर्शी होना चाहिए। यह भी कहा कि केंद्र में अलग से सहकारी मंत्रालय बनाने से जमीनी स्तर पर अर्थव्यवस्था को गति मिल सकेगी। सहकारी समितियां गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं बचत व ऋण सहकारी समितियां, सदस्यों को पूंजी तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती हैं। उदाहरण के तौर पर इथियोपिया जैसे गरीब देश में लगभग नौ लाख लोगों की आजीविका का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम सहकारिता ही है।

**स्थायी कृषि को बढ़ावा देना–** स्टेट आफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड (2018) के अनुसार हाल के साथियों से पता चला है कि दुनिया में भूखे लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। कुपोषण के विभिन्न आयामों को कम करने में भी सीमित प्रगति हुई है। सतत विकास के इस लक्ष्य का उद्देश्य भूख को समाप्त करना है। खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण उपलब्ध कराना है एवं 2030 तक संतुलित कृषि को बढ़ावा देना है। सहकारिताएं खाद्य असुरक्षा को कम एवं दूर करने में महत्वपूर्ण समाधान हो सकती हैं। सहकारी मॉडल को कृषि क्षेत्र में और अधिक दृढ़ता से लागू किए जाने की जरूरत है। हाल ही में केंद्रीय ग्रह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह

**अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक**

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

ने अपने एक भाषण में संबोधित करते हुए यह कहा कि भारत में शीघ्र ही कारपोरेट खेती की जगह को–आपरेटिव खेती की शुरुआत होगी और यह भी कहा कि केंद्र सरकार शीघ्र ही नई सहकारिता नीति लाने जा रही है और साथ ही देश में सहकारिता कॉलेज खोला जाएगा।

**हर वर्ग तक शिक्षा की पहुंच–** भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सहकारिता व ने शैक्षणिक गतिविधियों के जरिए अहम भूमिका का निर्वहन किया है। वर्तमान समय में देश भर में लगभग 10,000 सहकारितायें शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न है। कैंटीन सेवाएं, स्टेशनरी की आपूर्ति, पाठ्य पुस्तकों आदि सेवाओं में शैक्षणिक सहकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा रही है। हालांकि सहकारिताओं के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। इनमें शैक्षणिक स्टॉप पर अत्यधिक निर्भरता, क्षेत्रीय असंतुलन, एवं अनेकों प्रकार के संकटों को दूर करना होगा।

**जेंडर समानता के प्रयास–** भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की 2018 में जारी रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 21,493 महिला सहकारी समितियां है। सहकारी समितियों में महिलाओं की उपस्थिति से लैंगिक समानता में जुड़ी चुनौतियां कम हुई है। हमारे देश में ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने Women Dairy Cooperative Leadership Programme को शुरू किया है। भारत जैसे विकासशील देश में सहकारी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए उन्हें नीतिगत प्रक्रिया से जोड़ना भी आवश्यक होगा।

**साफ पानी एवं स्वच्छता–** देश के विभिन्न राज्यों में केरल में पेयजल आपूर्ति करने वाली सहकारी समितियों की स्थापना की गई। ये लगभग 14000 घरों में पीने का पानी उपलब्ध करातीं हैं। भारत देश में "जल जीवन मिशन" के तहत वाटर फिल्टरिंग प्लांट लगाने से लेकर वाटर एटीएम लगाने में सहकारी समितियों को वरीयता दी गई है। और इस क्षेत्र में काफी सफलता भी देखने को मिल रही है।

**अक्षय ऊर्जा उत्पादन–** भारत में सहकारी समितियों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में पहला कार्य सन 1950 में शुरू हुआ। United Nation Confrence On trade and Development के मुताबिक दुनिया भर में 57 करोड़ लोगों को अब तक बिजली नहीं मिल पाई है । 2 अरब 70 करोड़ लोगों के पास भोजन पकाने हेतु पर्याप्त स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता नहीं है। अतः इन समस्त गंभीर मुद्दों पर सहकारी समितियों के पास अनेक अवसर हैं जिनके माध्यम से इन समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी।

**सम्मानजनक रोजगार एवं आजीविका–** भारत में लगभग 12लाख महिलाओं को दुग्ध सहकारी समितियों में रोजगार मिला हुआ है। इससे न सिर्फ सहकारी मॉडल की सफलता देखी जा रही है बल्कि सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की संलग्नता के भी प्रत्यक्ष एवं सफल प्रमाण देखने को मिल रहे हैं। सहकारिता की भावना सामूहिक निर्णय पर आधारित होती है। ऐसे में सम्मानजनक रोजगार व आजीविका के लक्ष्य को हासिल करने का यह सबसे सशक्त माध्यम सिद्ध हो रहा है।

**जलवायु परिवर्तन–** 2015 के पेरिस समझौते के मुताबिक 2030 तक ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में 45: की कमी करनी होगी। सहकारिता के व्यापक क्षेत्र के बिना यह लक्ष्य हासिल करनाअसंभव है सहकारी संस्थाएं ग्लोबल इनिशिएटिव को भी अपना रही हैं। इन समस्त मुद्दों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भविष्य में निसंदेह सहकारिता मॉडल विभिन्न क्षेत्रों में एक प्रमुख मॉडल के रूप में उभरेगा।

**समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास–** रोजगार और सभी के लिए अच्छे काम को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता की भावना से मिलकर कार्य करने की जरूरत है सहकारिता एक लोकतांत्रिक विचारधारा है यह "सबका साथ एवं सबके विकास" की विचारधारा पर विश्वास करती है। कोविड–19 महामारी ने दशकों में सबसे खराब आर्थिक संकट को जन्म दिया लेकिन सहकारिता की भावना से प्रेरित होकर लोगों ने इस संकट को दूर करने में काफी सफलता हासिल की। उपर्युक्त वर्णित प्रमुख सतत विकास लक्ष्य जिनमें सहकारिता महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है।

**सतत विकास एवं सहकारी मॉडल–** भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सर्व समावेशी सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए सहकारिता, विकास पर त्वरित, समयबद्ध एवं व्यापक और परामर्शी कार्य योजना की आवश्यकता है। यह कार्य कठिन प्रतीत होता है लेकिन असंभावित नहीं है। सहकारिता ना सिर्फ आर्थिक गतिविधियों बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहुंच बना रही है। क्षमता का निर्माण, कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा, युवा और महिलाओं की भागीदारी को एकत्रित करने वाले समावेशी सहकारी मॉडल को बढ़ावा देने से वास्तविक सहकारी विकास मॉडलों की स्थापना हो सकती है। और संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्य की प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सकता है। यद्यपि आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत प्रसिद्ध है। सहकारिता माडल "वोकल फॉर लोकल" की प्रक्रिया कोअपनाकर अर्थव्यवस्था को मजबूती और आत्मनिर्भरता प्रदान करने में सफल सिद्ध हो सकता है।

**सतत विकास के एक मॉडल के रूप में सहकारी दृष्टिकोण–** सहकारी आंदोलन जो आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं के लिए सामाजिक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा है स्पष्ट रूप से मौजूद समस्याओं को चिन्हित कर रहा है सहकारी दृष्टिकोण की विचारधारा समुदाय और समाज में एकजुटता आपसी सहायता, भागीदारी और हित के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह विकास का प्रतीक है। जो भविष्य को ध्यान में रखता है अर्थात सतत विकास को ध्यान में रखता है। संतुलित विकास के एक मॉडल के रूप में सहकारी मॉडल पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि गरीब समुदायों का सहकारिता के साथ उद्यम संगठन न केवल बुनियादी बल्कि सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को भी पूरा करना चाहता है। यह स्थानीय विकास और वन संसाधनों के सतत उपयोग की भी अनुमति

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

प्रदान करता है। आर्थिक असमानता, शिक्षा का निम्न स्तर, शिशु कुपोषण और गरीबी से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कारक तथा पर्यावरण के क्षरण पर सीधे प्रभाव डालने वाले कारको के प्रति सहकारी समितियां, सहकारी केंद्र को अनुकूल परिस्थितियों को प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में सक्षम बनाती हैं। सहकारिता की भावना लोकतांत्रिक विचारधारा से ओतप्रोत है। सामाजिक समावेश को बढ़ावा देती है। और पर्यावरण की देखभाल करती है।

दुनिया की 30 लाख सहकारी समितियों में 8.55 लाख भारत में है। और लगभग 13 करोड लोग इससे सीधे रूप से जुड़े हैं। और भारत में 91% गांव में किसी न किसी रूप में सहकारी समितियां काम कर रही हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सरकारी समितियां विफल हो गई है। लेकिन उन्हें वैश्विक आंकड़े देखना चाहिए ,जो यह दर्शाता है कि कई देशों में सकल घरेलू उत्पाद में सहकारी समितियों का प्रमुख योगदान है। सहकारिता प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति का प्राण रही है। भारत ने विश्व को सहकारिता का विचार दिया है। सहकारी समितियों को संपन्न, समृद्ध और प्रासंगिक बनाने के लिए 'सहकारिता मंत्रालय' संभव सुधार लाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। सहकारी समितियां विभिन्न रूपों जैसे निष्पक्ष व्यापार में अधिक समावेशी और समान व्यापार संबंधों व मूल्य श्रृंखलाओं का समर्थन करती हैं। और नवीन दृष्टिकोणओं के माध्यम से निम्न कार्बन उत्पादन में भी योगदान करती हैं। दुनिया भर में संचालित सहकारी समितियां पर्यावरणीय क्षरण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ रही हैं। खाद्य सुरक्षा में योगदान दे रही हैं। स्थानीय समुदायों के अंदर वित्तीय पूंजी उपलब्ध करा रही हैं। एवं नैतिक श्रृंखला का निर्माण कर रही हैं। दुनिया भर के सहकारी समितियां सहकारिता का 100 वां अंतरराष्ट्रीय दिवस (02 जुलाई 2022) मना कर सहकारिता मॉडल को और अधिकजीवंतता प्रदान कर दी है।

स्थानीय ग्रामीण समुदायों की आजीविका को बनाए रखने में सहकारी समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। सहकारी समितियों के अपनाने से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोग रोजगार पैदा करने खाद्य उत्पादन को बढ़ाने,वंचित ,विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त करने और सामाजिक एकता एवं एकीकरण को बढ़ावा देने में कामयाब रहे हैं। जिससे उनकी आजीविका में सुधार हुआ। और गरीबी भी कम हुई है। यह देखा गया है कि सहकारी समितियों को कई प्रकार की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। जिसमें खराब प्रबंधन एवं प्रबंधन कौशल में कमी इत्यादि शामिल हैं। सहकारिता विविध जरूरतों को पूरा करती है जो किला विसर्जन से भरे हैं अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन दुनिया भर में सहकारी समितियों के लिए आवाज है जो इसका प्रतिनिधित्व करता है सहकारी समितियां कई अलग–अलग तरीकों से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संतुलन को बनाए रखने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय भूमिका निभाती हैं। सतत विकास लक्ष्यों को सहकारी समितियों के द्वारा कैसे कारगर बनाया जाए यह एक महत्वपूर्ण सोचनीय प्रश्न है। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरणीय गिरावट की दोहरी चुनौतियों का समाधान करने के लिए समाज का संतुलित विकास एवं आर्थिक संतुलन संबंधी विभिन्न कार्यक्रम आवश्यक है। इस महत्वपूर्ण बिंदु पर सहकारी समितियां सुधारवादी दृष्टिकोण के लिए ठोस योगदान दे सकती हैं लोकतांत्रिक विचारधारा के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग सुनिश्चित किये जा सकते हैं। सहकारी समितियों की गतिविधि का मुख्य फोकस, संतुलन की प्रक्रिया को बनाए रखते हुए समाज के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करना है। जीवन की रोजमर्रा की जरूरतों में लोगों को लाभान्वित करने के लिए सहकारी समितियों का करी तरह से उपयोग किया जा सकता है।

**IFFCO (Indian Farmer Fertilizer coopeerative)–** जलवायु परिवर्तन की तीव्रता को देखते हुए उर्वरक सहकारी समिति पंबिव अनेकों कुशल उत्पादों को विकसित करने के प्रयासों को तेज कर रही है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना संतुलित विकास की गति को भी तीव्रता प्रदान कर सके।

वर्तमान स्थिति को देखते हुए आने वाले समय में विश्व को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जिसके लिए सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी समिति संस्था इन समस्याओं को दूर करने में काफी हद तक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इफको जैविक खाद विकसित करने पर भी काम कर रही है जो मिट्टी की बनावट में सुधार कर सके एवं पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव भी ना पड़े। डॉ वंदना शिवा नें ICA सम्मेलन में ग्रह (Earth)को बचाने में मदद करने के लिए सहकारी समितियों का आह्वान किया।

**जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को कम करने में सहकारिता मॉडल का योगदान–**

1. सहकारी समितियां सामूहिक रूप से बढ़ते तापमान जल संसाधनों का ह्रास, भूमि एवं संसाधनों की गिरावट जैसे उभरते प्रभाव के लिए समाधान प्रदान करती है।
2. सहकारी समितियों के द्वारा पर्यावरणीय सामाजिक एजेंडे को स्पष्ट रुप से अपनाना व्यवहार्यता एवं जीवन शक्ति में योगदान करता है।
3. सहकारी समितियां प्राकृतिक संसाधनों के स्वतंत्र प्रबंधन में कई तरह से योगदान करती हैं। ये अपने अभिनव कौशल के साथ वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने और ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा दक्षता एवं निम्न उत्सर्जन के सतत लक्ष्यों को पूरी तरह से मदद करने की क्षमता रखतीं हैं।

**निष्कर्ष–** स्पष्ट है कि सहकारिता पहले से ही सतत विकास लक्ष्य द्वारा इंगित उद्देश्यों और लक्ष्यों की दिशा में निरंतरता के साथ काम करते हुए आगे बढ़ती रही है। सहकारिता द्वारा किए जा रहे योगदान को व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों स्तरों पर शामिल किया जा रहा है। जैसे कि लैंगिक समानता, भुखमरी समाप्त करना ,संतुलित उत्पादन और उपभोग गरीबी उन्मूलन इत्यादि। हालांकि इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं मान लेना चाहिए कि सहकारी समितियों के अलावा अन्य किन्ही माध्यमों से इन सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः सहकारी मॉडल भी अन्य मॉडलों की तरह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक उपयोगी

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

मॉडल की तरह ही सहायक सिद्ध हो रहा है। सहकारिता को योजनाबद्ध आर्थिक विकास के पसंदीदा उपकरण माना गया एवं यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विशेषीकृत क्षेत्र बनकर उभरा है। वर्तमान में हमारी सरकार ने "सहकारिता मंत्रालय" का गठन करके सहकारिता को एक नई दिशा और गति प्रदान की है। सहकारिता की भूमिका ने वैश्वीकरण और उदारीकरण के बदलते परिदृश्य में अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में एक नए आयाम को प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। सहकारितायें अपने लोकतांत्रिक संरचनाओं के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के समान प्रबंधन एवं कुशल उपयोग को सुनिश्चित करके उत्पादन और खपत के लिए योगदान दे सकती हैं। सदस्यों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सहकारी समितियां अपने सदस्यों के सतत विकास के लिए काम करतीं हैं। सहकारी आंदोलन नें पर्यावरण संरक्षण की भूमिका को अपने मूल्यों और सिद्धांतों के भीतर निहित मान्यता के रूप में महत्त्व प्रदान किया है।

## संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कुमार, आलोक (2021) सहकारिता से समृद्धिः बुक्स क्लीनिक पब्लिकेशन।
2. सिंह कटार, सिसोदिया अनिल (2018) ग्रामीण विकासःसिद्धांत,नीतियां एवं प्रबंधनः सेज पब्लिकेशन।
3. खुराना ललिता, ग्रामीण भारत में सामाजिक बदलाव ,अक्टूबर 2021, कुरुक्षेत्र।
4. सिंह, कुमार अरुण (2017) मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियां।
5. भार्गव, पंडित शंकर प्रसाद (1935).भारतीय सहकारिता आंदोलनःदारागंज (इलाहाबाद) पब्लिकेशन।
6. नेहरू, जवाहरलाल, ग्राम स्वराज का नया रूप : सहकारिता, नवीन प्रेस दिल्ली।
7. कोरेथ जार्ज, बड़ेहरा किरण, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण,सेज पब्लिकेशन।
8. शर्मा, विद्यासागर (1960) आधुनिक सहकारिता, सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, नई दिल्ली ।
9. खुराना ललिता, सहकारिता, जनवरी 2023, कुरुक्षेत्र।
1-. www.pib.nic.in
11. www.ncui.in
12. www.ncdc.ac.in.
13. www.nddb.ac.in.
14. कमल कुलश्रेष्ठ, हमारा पारिस्थितिक तंत्र, अक्टूबर 2022, योजना।
15. आहुजा राम, सामाजिक अनुसंधानः रावत पब्लिकेशन।

*****